आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति समुदायों के मध्य क्षेत्रीय विषमता: समग्र सूचकांक आधारित अध्ययन

Anoop Kumar Singh[1], Dr. Ankit Singh[2]

[1]Research Scholar, Department of Geography, D.A.V Degree College, Azamgarh
[2]Assistant Professor, Department of Geography, Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University Gorakhpur

सारांश

यह अध्ययन आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति समुदायों के संदर्भ में क्षेत्रीय विषमता की प्रकृति, स्तर और सामाजिक-आर्थिक आयामों का विश्लेषण करता है। अध्ययन में जनगणना 2011 के ब्लॉक-स्तरीय आँकड़ों के आधार पर 22 सामुदायिक विकास खंडों का मूल्यांकन किया गया है। विकास स्तर को मापने के लिए समग्र विकास सूचकांक तैयार किया गया, जिसमें लिंगानुपात, साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, मुख्य कृषि मजदूर तथा सीमांत कृषि मजदूर जैसे संकेतकों को सम्मिलित किया गया। सात संकेतक और 22 ब्लॉक-स्तरीय विश्लेषण आधार के रूप में दिए गए हैं।

विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ के विभिन्न ब्लॉकों में विकास का स्तर समान नहीं है। लालगंज, पल्हनी और मिर्जापुर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करने वाले ब्लॉक के रूप में सामने आते हैं, जबकि महराजगंज, कोइलसा और हरैया विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए पाए गए। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि अनुसूचित जाति जनसंख्या का अधिक प्रतिशत अपने-आप में निम्न विकास का कारण नहीं है; बल्कि शिक्षा, अवसंरचना, आजीविका संरचना, स्थानीय शासन, भौगोलिक स्थिति और विकास योजनाओं की प्रभावशीलता जैसे कारक भी विकास परिणामों को प्रभावित करते हैं। सहसंबंध एवं प्रतिगमन विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि जातीय संरचना विकास का एक महत्त्वपूर्ण कारक है, परंतु वह अकेला निर्णायक तत्व नहीं है। इस प्रकार, आजमगढ़ में क्षेत्रीय विषमता को समझने के लिए सामाजिक संरचना और स्थानिक विकास दोनों को साथ-साथ देखना आवश्यक है।

Keywords : क्षेत्रीय विषमता, अनुसूचित जाति, समग्र विकास सूचकांक, सामाजिक-आर्थिक विकास.

1- क्षेत्रीय विषमता की संकल्पना एवं आजमगढ़ जनपद में विश्लेषण

क्षेत्रीय विषमता से तात्पर्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में **आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक (अवसंरचनात्मक) विकास के असमान स्तरों** से है (Williamson, 1965)। ऐसी असंतुलन की स्थिति विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में पाई जाती है, जो आमतौर पर आय, साक्षरता, औद्योगिकीकरण और मूलभूत सेवाओं की उपलब्धता जैसे संकेतकों में परिलक्षित होती है (Bakshi आदि, 2015)। अक्सर ऐसा तब होता है जब कुछ क्षेत्रों को संसाधनों की उपलब्धता, औपनिवेशिक विरासत या नीतिगत प्राथमिकता के कारण आरंभिक लाभ प्राप्त हो जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों की **तुलनात्मक उपेक्षा** होती है (Nagaraja एवं Veerabhadrappa, 2018)।

एक महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि **राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया के साथ-साथ क्षेत्रीय विषमता भी विकसित होती है**। प्रारंभ में आर्थिक गतिविधियाँ कुछ सीमित एवं समृद्ध केंद्रों में केंद्रित हो जाती हैं। कालांतर में यदि अवसंरचना और मानव संसाधन में निवेश बाहरी क्षेत्रों की ओर फैलता है, तो ये लाभ व्यापक क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं (World Bank, 2009)। हालाँकि, यह प्रसार कितनी गति से और किस सीमा तक होता है, यह भिन्न-भिन्न देशों में अलग-अलग होता है। उदाहरणस्वरूप, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, जहाँ कभी क्षेत्रीय समरूपता की प्रवृत्ति थी, 1980 के दशक के बाद औद्योगीकरण के क्षय और श्रम गतिशीलता की कमी के चलते यह प्रवृत्ति धीमी हो गई (IMF, 2019)। वहीं, कई विकासशील देशों में मिला-जुला परिदृश्य देखा गया—कुछ राज्य या प्रांत औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के केंद्र बन गए, कुछ कृषि आधारित और संसाधन-वंचित रह गए, जबकि कुछ क्षेत्र स्थानीय शासन, भौगोलिक प्रतिबंधों, या अवसंरचना की कमी के अनुसार इन दो अवस्थाओं के बीच झूलते रहे।

ऐतिहासिक रूप से, नवस्वतंत्र या सुधारशील देशों ने **लंबे समय से व्याप्त असंतुलनों को दूर करने हेतु विविध रणनीतियाँ** अपनाई हैं—जैसे लक्षित औद्योगिक प्रोत्साहन, विशेष विकास अनुदान, या बड़े पैमाने की अवसंरचना परियोजनाएँ (Kurian, 2000)। यद्यपि बेहतर संपर्क और मूलभूत सेवाएँ वंचित क्षेत्रों को लाभ पहुँचा सकती हैं, इस बात को लेकर विमर्श बना हुआ है कि **स्थान-आधारित (place-based)** नीतियाँ अधिक प्रभावी हैं या **व्यक्ति-आधारित (people-based)** दृष्टिकोण।

स्थान-आधारित रणनीतियाँ जैसे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना या विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs) बनाना, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देती हैं। वहीं **व्यक्ति-आधारित नीतियाँ** जैसे प्रत्यक्ष आय समर्थन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी व्यापक योजनाएँ, निवास स्थान की परवाह किए बिना नागरिकों को सशक्त बनाने पर केंद्रित होती हैं। इन दोनों दृष्टिकोणों के अपने-अपने लाभ और सीमाएँ हैं, और अधिकांश राष्ट्रीय सरकारें समावेशी व संतुलित विकास हेतु इनका संयोजन अपनाती हैं (Naresh Kumar एवं Ritu Rani, 2019)।

संक्षेप में, **क्षेत्रीय विषमता आज भी वैश्विक विकास की एक गंभीर चुनौती बनी हुई है**। हालाँकि यह कभी-कभी आर्थिक संकेंद्रण (agglomeration) और विशेषीकरण (specialization) की सामान्य प्रक्रिया को दर्शा सकती है, लेकिन यदि इसे नियंत्रित न किया जाए तो यह सामाजिक असंतोष, प्रवासन दबाव और देश की मानव एवं भौतिक संसाधनों की अप्रभावी उपयोगिता को जन्म दे सकती है। अतः, क्षेत्रीय विषमता को कम करने के लिए आवश्यक है कि स्थानिक रूप से जोड़ने वाले **अवसंरचना निवेश**, **शासन में सुधार** और **स्थानीय संदर्भों के अनुसार मानव संसाधन विकास** की रणनीतियों को विवेकपूर्ण ढंग से अपनाया जाए (Frankel, 2005; World Bank, 2009; IMF, 2019)।

2- समग्र सूचकांक (Composite Index) की गणना

विकास के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु **समग्र सूचकांक** (Composite Index – CI) की गणना एक निर्धारित संकेतक समूह के आधार पर की जाती है। इस विश्लेषण के लिए **सात संकेतकों** का चयन किया गया है, जो निम्नलिखित हैं:

1. लिंगानुपात (Sex Ratio)
2. साक्षरता दर (Literacy Rate)
3. महिला साक्षरता दर (Female Literacy Rate)
4. अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत (SC Population %)
5. अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत (ST Population %)
6. मुख्य कृषि मज़दूरों का प्रतिशत (Main Agricultural Labour %)
7. सीमांत कृषि मज़दूरों का प्रतिशत (Marginal Agricultural Labour %)

2.1 - समग्र सूचकांक की गणना दो चरणों में की जाती है:

चरण 1: सामान्यीकरण (Normalization)

प्रत्येक संकेतक को 0 से 1 के पैमाने पर **सामान्यीकृत** किया जाता है, जिससे सभी संकेतकों को तुलनात्मक रूप से मापा जा सके।

चरण 2: औसतन गणना

सभी सामान्यीकृत मूल्यों का **औसत** निकालकर एकल समग्र स्कोर (Composite Score) प्राप्त किया जाता है, जो प्रत्येक इकाई (जैसे: ब्लॉक) के लिए विकास स्तर को दर्शाता है।

सामान्यीकरण हेतु सूत्र

समग्र सूचकांक (Composite Index) की गणना के लिए सभी चयनित संकेतकों को 0 से 1 के पैमाने पर सामान्यीकृत किया गया। सामान्यीकरण की प्रक्रिया इसलिए आवश्यक है क्योंकि सभी संकेतक अलग-अलग इकाइयों और माप-स्तरों में व्यक्त होते हैं। इस अध्ययन में संकेतकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया—सकारात्मक संकेतक और नकारात्मक संकेतक।

सकारात्मक संकेतक वे हैं जिनका उच्च मान विकास की बेहतर स्थिति को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर और लिंगानुपात जैसे संकेतकों का अधिक होना सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से अनुकूल माना गया है। ऐसे संकेतकों के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया:

$$\text{Normalized}(Xi) = \frac{(Xi - Xmin)}{(Xmax - Xmin)}$$

जहाँ,

Xi= अध्ययन क्षेत्र का मूल मान

Xmin = पूरे डेटा सेट में न्यूनतम मान

Xmax= पूरे डेटा सेट में अधिकतम मान

इस सूत्र के प्रयोग से जिस ब्लॉक का मान अधिक होता है, उसे अधिक सामान्यीकृत स्कोर प्राप्त होता है, जो बेहतर विकास स्थिति को दर्शाता है।

नकारात्मक संकेतक वे हैं जिनका उच्च मान पिछड़ेपन, निर्भरता या सामाजिक-आर्थिक कमजोरी को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, मुख्य कृषि मजदूरों का प्रतिशत तथा सीमांत कृषि मजदूरों का प्रतिशत अधिक होने पर यह कृषि मजदूरी और अस्थिर रोजगार पर अधिक निर्भरता को दर्शाता है। ऐसे संकेतकों के लिए उल्टा सामान्यीकरण किया गया, ताकि उच्च वास्तविक मान को कम विकास स्कोर प्राप्त हो। इसके लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया गया:

$$\text{Normalized}(Xi) = \frac{(Xmax - Xi)}{(Xmax - Xmin)}$$

इस सूत्र के अनुसार, जिस ब्लॉक में नकारात्मक संकेतक का मान अधिक होगा, उसका सामान्यीकृत स्कोर कम होगा; जबकि जिस ब्लॉक में इस संकेतक का मान कम होगा, उसका सामान्यीकृत स्कोर अधिक होगा। इस प्रकार सामान्यीकरण के बाद सभी संकेतक एक समान दिशा में व्याख्यायित किए जा सकते हैं, अर्थात् उच्च सामान्यीकृत मान बेहतर विकास स्थिति को दर्शाता है।

सभी सात संकेतकों के सामान्यीकृत मान प्राप्त करने के बाद प्रत्येक ब्लॉक के लिए इनका सरल औसत निकाला गया। यही औसत मान उस ब्लॉक का समग्र विकास सूचकांक या Composite Index माना गया।

$$CI = \frac{1}{N}\sum_{J=1}^{N} \text{Normalized}(Xij)$$

जहाँ:

- CI = समग्र सूचकांक
- N = संकेतकों की कुल संख्या (**यहाँ N = 7**)
- Normalized(Xij) = इकाई i के लिए j-वें संकेतक का सामान्यीकृत मान
- ∑ = सभी संकेतकों के सामान्यीकृत मानों का योग

इस प्रकार प्राप्त समग्र सूचकांक 0 से 1 के बीच होता है। 1 के निकट मान अपेक्षाकृत बेहतर विकास स्थिति को दर्शाता है, जबकि 0 के निकट मान अपेक्षाकृत निम्न विकास स्थिति को इंगित करता है।

Table 1: Computation of composite Index based on Census data, 2011

Independent Variables	**Minimum Value**	**Maximum Value**	**Methods**
Sex Ratio	938	1084	(X−Xmin)/(Xmax−Xmin)
Literacy Rate (%)	64.84	74.02	(X−Xmin)/(Xmax−Xmin)
Female Literacy Rate (%)	53.91	65.29	(X−Xmin)/(Xmax−Xmin)
SC Population (%)	20.25	40.35	(Xmax−X)/(Xmax−Xmin)*
ST Population (%)	0.01	0.54	(Xmax−X)/(Xmax−Xmin)*
Main Agricultural Labourers (%)	2.57	5.33	(Xmax−X)/(Xmax−Xmin)*
Marginal Agricultural Labourers (%)	4.13	9.36	(Xmax−X)/(Xmax−Xmin)*

Source: Census of India, 2011

Table 2. Block-wise Composite Development Index and Selected Indicators, Azamgarh District (2011)

Sl. No.	**C.D. Block**	**Sex Ratio**	**Literacy Rate**	**Female Literacy Rate**	**SC Population**	**ST Population**	**Main Agricultural Labours**	**Marginal Agricultural Labours**	**Composite Score**	**Rank**
1	Lalganj	1075	71.48	61.48	32.18	0.18	3.02	5.6	0.69	1
2	Palhani	938	73.79	63.04	20.25	0.54	2.71	4.13	0.68	2
3	Mirzapur	1039	74.02	65.29	24.49	0.01	2.84	4.78	0.67	3
4	Palhna	1081	69.02	58.34	28.39	0.51	3.36	7.01	0.62	4
5	Mohammadpur	1045	73.13	64.02	26.95	0.24	4.77	5.03	0.62	5

6	Thekma	1074	69.42	59.08	40.35	0.06	3.43	6.5	0.6	6
7	RaniKi Sarai	1008	71.59	60.54	28.35	0.13	2.57	6.47	0.57	7
8	Tarwa	1033	70.27	59.31	29.28	0.32	3.58	7.61	0.53	8
9	Azmatgarh	1018	71.18	61.41	24.99	0.24	2.89	8.25	0.52	9
10	Phulpur	1042	71.33	61.1	23.46	0.02	3.02	6.43	0.52	10
11	Bilariyaganj	999	71.6	61.82	28.29	0.18	4.66	5.77	0.5	11
12	Atraulia	1044	71.6	60.69	23.28	0.04	3.31	7.13	0.49	12
13	Sathiyaon	976	68.35	60	23.44	0.2	3.01	4.77	0.49	13
14	Mehnagar	1030	69	57.62	33.75	0.48	5.33	7.24	0.48	14
15	Pawai	1017	71.48	61.19	24.12	0.14	3.83	6.9	0.48	15
16	Jahanaganj	1003	69.76	58.66	31.87	0.4	4.07	8.58	0.47	16
17	Martinganj	1084	68.51	58.34	21.3	0.22	3.56	9.36	0.41	17
18	Tahbarpur	1038	69.62	57.74	24.33	0.01	2.79	8.69	0.4	18
19	Ahiraula	1004	69.76	58.7	22.54	0.17	3.85	8.12	0.37	19
20	Haraiya	1016	67.84	57.67	24.87	0.07	3.48	7.59	0.36	20
21	Koilsa	1045	69.87	58.68	22.09	0.04	4.2	9.28	0.33	21
22	Mahrajganj	1017	64.84	53.91	23.25	0.23	3.31	7.9	0.3	22

3- विकास संकेतकों में ब्लॉक-स्तरीय विषमता

आजमगढ़ जिले के 22 सामुदायिक विकास खंडों में क्षेत्रीय विषमता को समझने के लिए जनगणना 2011 के आँकड़ों पर आधारित एक समग्र विकास सूचकांक तैयार किया गया। इसमें लिंगानुपात, कुल साक्षरता, महिला साक्षरता, अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या, मुख्य कृषि मजदूर और सीमांत कृषि मजदूर जैसे सात संकेतकों को शामिल किया गया। इन संकेतकों को सामान्यीकृत कर प्रत्येक ब्लॉक का समग्र स्कोर निकाला गया, जहाँ उच्च स्कोर बेहतर सामाजिक–आर्थिक स्थिति को दर्शाता है।

परिणामों से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ जिले में ब्लॉक-स्तर पर विकास में पर्याप्त असमानता है। लालगंज ब्लॉक 0.69 स्कोर के साथ सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि महराजगंज 0.30 स्कोर के साथ सबसे निचले स्थान पर है। लालगंज, पल्हनी और मिर्जापुर जैसे ब्लॉकों में साक्षरता, महिला साक्षरता और गैर-कृषि अवसरों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। पल्हनी की बेहतर स्थिति आंशिक रूप से आजमगढ़ शहर के निकट होने और शहरी सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ी है। लालगंज विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या लगभग 32 प्रतिशत होने के बावजूद विकास सूचकांक सर्वाधिक है। यह दर्शाता है कि अधिक SC जनसंख्या अपने-आप निम्न विकास का कारण नहीं बनती, यदि अवसंरचना, संपर्क-सुविधा और प्रशासनिक समर्थन बेहतर हों।

इसके विपरीत, महराजगंज, कोइलसा और हरैया सबसे पिछड़े ब्लॉकों में आते हैं। महराजगंज में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता दोनों कम हैं, जबकि कोइलसा में सीमांत कृषि मजदूरों की अधिकता आर्थिक असुरक्षा और अधरोज़गारी को दर्शाती है। कोइलसा का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि पिछड़ापन केवल जातीय संरचना से नहीं, बल्कि व्यापक आर्थिक और कृषि संकट से भी जुड़ा हो सकता है।

मध्यम श्रेणी के ब्लॉकों में भी विविधता पाई गई। ठेकमा में SC जनसंख्या सबसे अधिक, लगभग 40.3 प्रतिशत, होने के बावजूद इसका विकास स्तर अपेक्षाकृत बेहतर है। इसके विपरीत, मेहनगर में उच्च SC जनसंख्या के साथ कम साक्षरता और कृषि मजदूरी पर अधिक निर्भरता दिखाई देती है, जिससे इसका विकास स्तर नीचे रहता है।

इस प्रकार, आजमगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या और विकास स्तर के बीच कोई सीधा या मजबूत रेखीय संबंध नहीं मिलता। कुछ SC-प्रधान ब्लॉक बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ कम SC जनसंख्या वाले ब्लॉक भी पिछड़े हैं। इससे स्पष्ट है कि क्षेत्रीय विकास केवल जातीय संरचना से निर्धारित नहीं होता, बल्कि साक्षरता, अवसंरचना, रोजगार, भौगोलिक स्थिति, शासन और स्थानीय विकास हस्तक्षेप जैसे अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से निर्मित होता है।

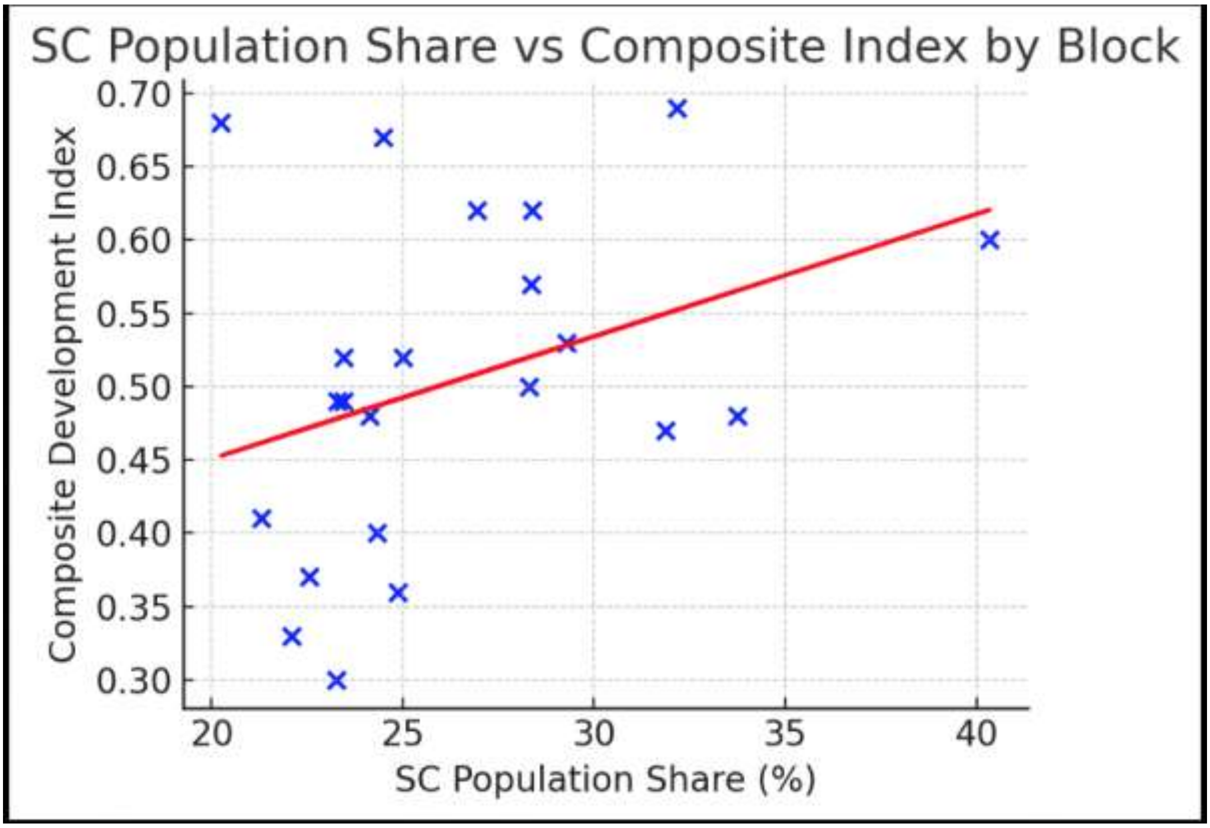

Figure 1: Scatterplot of SC Population Share (%) vs. Composite Development Index for Azamgarh Blocks (2011). Each point represents one block. A higher composite index indicates better development outcomes. The red line is a linear fit (trend line) showing a weak, slightly positive correlation.

चित्र 1 से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ में अनुसूचित जाति जनसंख्या और विकास स्तर के बीच कोई स्पष्ट ऋणात्मक सहसंबंध नहीं पाया जाता। इससे संकेत मिलता है कि क्षेत्रीय विकास केवल जातीय संरचना से निर्धारित नहीं होता, बल्कि भौगोलिक स्थिति, शहरी केंद्रों की निकटता, शासन व्यवस्था, अवसंरचना और स्थानीय विकास कार्यक्रमों जैसे अनेक कारकों से प्रभावित होता है। ठेकमा और लालगंज जैसे उच्च SC जनसंख्या वाले ब्लॉकों का बेहतर प्रदर्शन तथा कोइलसा और महराजगंज जैसे कम SC प्रतिशत वाले ब्लॉकों का पिछड़ापन इस बात को पुष्ट करता है कि SC जनसंख्या विकास का एक कारक है, लेकिन एकमात्र निर्धारक नहीं।

फिर भी, निचली विकास रैंकिंग वाले कई ब्लॉकों में SC जनसंख्या 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई है। इन क्षेत्रों में महिला साक्षरता अपेक्षाकृत कम और सीमांत कृषि श्रमिकों पर निर्भरता अधिक दिखाई देती है। इससे संकेत मिलता

है कि जातीय वंचना, कमजोर शैक्षणिक अवसर, गैर-कृषि रोजगार की कमी और सामाजिक अवरोध कुछ ब्लॉकों में विकास को प्रभावित कर सकते हैं। अतः आगे का सहसंबंध विश्लेषण इन संबंधों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने में सहायक होगा।

4- सांख्यिकीय विश्लेषण: जाति और विकास के बीच संबंध

इस अध्ययन में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और अनुसूचित जाति SC जनसंख्या प्रतिशत के बीच संबंधों को समझने के लिए **पियर्सन सहसंबंध गुणांक (Pearson Correlation Coefficient)** का प्रयोग किया गया है। **पियर्सन सहसंबंध गुणांक (r)** दो चर के बीच **रेखीय संबंध की शक्ति और दिशा** को मापता है। इसका मान **(-1 से +1)** के बीच होता है। यदि **r = +1** हो, तो यह दर्शाता है कि दोनों चर के बीच **पूर्ण धनात्मक संबंध** है; यदि **r = -1** हो, तो यह **पूर्ण ऋणात्मक संबंध** को दर्शाता है, तथा यदि **r = 0** हो तो कोई भी रेखीय संबंध नहीं होता।

पियर्सन सहसंबंध गुणांक का गणितीय सूत्र:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}}$$

जहाँ:

- r = पियर्सन सहसंबंध गुणांक
- x_i = प्रथम चर (उदा. एससी जनसंख्या प्रतिशत) के लिए i-वें अवलोकन का मान
- y_i = द्वितीय चर (जैसे साक्षरता, रोजगार आदि) के लिए i-वें अवलोकन का मान
- $\bar{x}$ = चर x के मानों का औसत
- $\bar{y}$ = चर y के मानों का औसत
- n = कुल अवलोकनों की संख्या

इस अध्ययन में पियर्सन सहसंबंध गुणांक का प्रयोग निम्न चरणों में किया गया है:

1. सर्वप्रथम ब्लॉक स्तरीय आँकड़ों को एकत्र किया गया और उन्हें व्यवस्थित किया गया।
2. प्रत्येक चयनित संकेतक (जैसे: साक्षरता दर, कृषि श्रमिकों की संख्या, समग्र विकास सूचकांक) और एससी जनसंख्या प्रतिशत के बीच Pearson correlation की गणना की गई।
3. प्राप्त सहसंबंध मानों की सांख्यिकीय सार्थकता (statistical significance) का परीक्षण किया गया, जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाया गया संबंध आकस्मिक है या सांख्यिकीय रूप से अर्थपूर्ण।

इस पद्धति के प्रयोग से अध्ययन में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों और अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच मौजूद संभावित संबंधों को स्पष्टता से समझने में सहायता मिली।

ब्लॉक स्तर पर अनुसूचित जाति SC जनसंख्या के प्रतिशत और सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के बीच संबंध को अधिक **कठोर और व्यवस्थित रूप से जांचने** के लिए, हमने **सहसंबंध विश्लेषण (correlation analysis)** और **सरल प्रतिगमन परीक्षण (simple regression tests)** किए। इस विश्लेषण के लिए **तालिका 3.1** से प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया।

तालिका 2 में एससी जनसंख्या प्रतिशत और कुछ **प्रमुख विकास संकेतकों** — जैसे **कुल साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, मुख्य एवं सीमांत कृषि श्रमिकों के प्रतिशत** — के बीच **पियर्सन सहसंबंध गुणांक (Pearson Correlation Coefficients)** को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।
इसके अतिरिक्त, हमने **समग्र विकास सूचकांक (Composite Development Index)** के साथ भी एससी जनसंख्या के सहसंबंध को देखा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जातीय संरचना सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन को किस हद तक प्रभावित करती है।

Indicator	**Pearson's r (correlation with SC% share)**
Overall Literacy Rate (%)	–0.06 (very weak negative)
Female Literacy Rate (%)	–0.08 (very weak negative)
% Main workers as Agri. Labourers	+0.29 (moderate positive)
% Marginal workers as Agri. Labourers	–0.08 (very weak negative)
Composite Development Index (0–1)	+0.36 (moderate positive)

Sources: Computed from Census 2011 data. None of the correlations above (except with Composite Index) are statistically significant at $p<0.05$; they are shown to indicate direction and strength.

सहसंबंध विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि आजमगढ़ जनपद में अनुसूचित जाति जनसंख्या और विकास संकेतकों के बीच संबंध सरल या प्रत्यक्ष नहीं है। SC जनसंख्या प्रतिशत और कुल साक्षरता दर के बीच बहुत कमजोर ऋणात्मक संबंध पाया गया, जबकि महिला साक्षरता के साथ भी संबंध लगभग शून्य के निकट रहा। इससे स्पष्ट है कि किसी ब्लॉक में SC जनसंख्या अधिक होना स्वतः कम साक्षरता का संकेत नहीं देता। ठेकमा जैसे उच्च SC जनसंख्या वाले ब्लॉकों में अपेक्षाकृत बेहतर साक्षरता पाई गई, जबकि कोइलसा जैसे कम SC प्रतिशत वाले ब्लॉकों में साक्षरता निम्न रही।
SC प्रतिशत और मुख्य कृषि श्रमिकों के बीच हल्का धनात्मक सहसंबंध पाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि SC सघन ब्लॉकों में कृषि मजदूरी पर निर्भरता कुछ अधिक हो सकती है। यह दलित समुदायों की भूमि-विहीनता और खेतिहर मजदूरी से जुड़ी ऐतिहासिक स्थिति को दर्शाता है। इसके विपरीत, सीमांत कृषि श्रमिकों और SC प्रतिशत के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं पाया गया।
रोचक रूप से, SC प्रतिशत और समग्र विकास सूचकांक के बीच हल्का धनात्मक संबंध पाया गया। यह निष्कर्ष पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि अधिक SC जनसंख्या वाले क्षेत्र अनिवार्य रूप से पिछड़े होते हैं। लालगंज और ठेकमा जैसे ब्लॉकों ने इस प्रवृत्ति को प्रभावित किया, जहाँ SC जनसंख्या अधिक होने के बावजूद विकास सूचकांक अपेक्षाकृत बेहतर रहा।
प्रतिगमन विश्लेषण से भी यह स्पष्ट हुआ कि SC प्रतिशत अकेले किसी ब्लॉक के विकास स्तर का मजबूत पूर्वानुमानक नहीं है। जब साक्षरता दर को नियंत्रण चर के रूप में शामिल किया गया, तो SC प्रतिशत का प्रभाव और कमजोर हो गया। इससे संकेत मिलता है कि विकास पर जातीय संरचना का प्रभाव प्रत्यक्ष न होकर शिक्षा, रोजगार संरचना, भूमि स्वामित्व और अवसंरचना जैसे मध्यस्थ कारकों के माध्यम से कार्य करता है।
सारांशतः, आजमगढ़ में ब्लॉक-स्तरीय विकास कई कारकों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित होता है। SC जनसंख्या की अधिकता कुछ चुनौतियों, विशेषकर कृषि मजदूरी पर निर्भरता, से जुड़ी हो सकती है; परंतु यह स्वतः निम्न विकास को

निर्धारित नहीं करती। इसलिए SC-प्रधान क्षेत्रों के लिए एक समान नीति अपनाने के बजाय शिक्षा, रोजगार, भूमि-सुरक्षा और अवसंरचना से जुड़े विशिष्ट अभावों को पहचानकर लक्षित योजनाएँ बनाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

- आजमगढ़ जनपद में क्षेत्रीय विषमता का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि जिले के भीतर विकास की स्थिति समान नहीं है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनसंख्या के संदर्भ में यह असमानता अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। कई पिछड़े ब्लॉकों में ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों की अधिक उपस्थिति पाई जाती है, जबकि अपेक्षाकृत विकसित ब्लॉकों में बेहतर संपर्क, प्रशासनिक सक्रियता और संसाधनों की उपलब्धता के कारण समग्र विकास की स्थिति बेहतर है।
- अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि SC जनसंख्या और क्षेत्रीय पिछड़ेपन का संबंध पूर्णतः नियतात्मक नहीं है। कुछ ऐसे ब्लॉक, जहाँ अनुसूचित जाति जनसंख्या अधिक है, वहाँ विकास के सकारात्मक संकेत भी दिखाई देते हैं। यह दर्शाता है कि उचित नीति समर्थन, संसाधन उपलब्धता और प्रभावी प्रशासन के माध्यम से ऐतिहासिक वंचनाओं को कम किया जा सकता है।
- समग्र सूचकांक और सांख्यिकीय विश्लेषण से साक्षरता में अंतर, सीमांत श्रमिकों की अधिकता, रोजगार के सीमित अवसर और आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसी प्रमुख समस्याएँ सामने आईं। ये समस्याएँ दर्शाती हैं कि क्षेत्रीय विषमता केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना से भी गहराई से जुड़ी हुई है।
- इसलिए आजमगढ़ जैसे जनपदों में विकास के लिए एक समान नीति पर्याप्त नहीं होगी। प्रत्येक ब्लॉक की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संदर्भ-विशिष्ट और लक्षित रणनीतियाँ बनानी होंगी। विशेष रूप से पिछड़े ब्लॉकों और उनमें निवास करने वाले वंचित समुदायों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- अध्ययन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शैक्षणिक अवसंरचना को मजबूत करना, गैर-कृषि रोजगार के अवसर बढ़ाना, भूमि और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा अनुसूचित जाति समुदायों के लिए सकारात्मक भेदभाव की नीतियों को प्रभावी बनाना क्षेत्रीय विषमता को कम करने के महत्वपूर्ण उपाय हो सकते हैं।
- थीसिस के व्यापक संदर्भ में आजमगढ़ का उदाहरण यह स्पष्ट करता है कि क्षेत्रीय विषमता को समझने के लिए सामाजिक संरचना को शामिल करना आवश्यक है। जब तक यह नहीं देखा जाएगा कि विकास का लाभ किन समूहों तक पहुँचा और कौन पीछे छूट गया, तब तक क्षेत्रीय असमानता का विश्लेषण अधूरा रहेगा।
- अंततः, आजमगढ़ का समावेशी विकास इस बात पर निर्भर करेगा कि जिले के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली दलित आबादी को शिक्षा, रोजगार, अवसंरचना और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कितनी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि ब्लॉक-स्तर पर विषमताओं की निरंतर निगरानी की जाए और योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से वंचित समुदायों तक पहुँचाया जाए, तो आजमगढ़ समावेशी क्षेत्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।

REFERENCES

1. Bakshi, S., Chawla, A., & Shah, M. (2015). Regional disparities in India: A moving frontier. Economic and Political Weekly, 50(1), 44–52. https://www.jstor.org/stable/24481240

2. Bhattacharya, B. B., & Sakthivel, S. (2004). Regional growth and disparity in India: Comparison of pre- and post-reform decades. Economic and Political Weekly, 1071–1077.
3. Cashin, P., & Sahay, R. (1996). Internal migration, center-state grants, and economic growth in the states of India. IMF Staff Papers, 43(1), 123–171.
4. Census of India. (2011). Primary Census Abstract – Uttar Pradesh: Azamgarh district data. Office of the Registrar General & Census Commissioner, Government of India, New Delhi.
5. Dehury, B., & Mohanty, S. K. (2015). Regional estimates of multidimensional poverty in India. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 9(2015-36), 1–35.
6. Ghosh, M. (2008). Economic reforms, growth and regional divergence in India. Margin: The Journal of Applied Economic Research, 2(3), 265–285.
7. Government of India. (2013). Statistical profile of Scheduled Castes in Uttar Pradesh. Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi.
8. Hindustan Times. (2023). Uttar Pradesh's regional disparities: Western districts lead in development indicators, eastern districts lag behind. Retrieved from https://www.hindustantimes.com
9. Kapur, D., Prasad, C. B., Pritchett, L., & Babu, D. S. (2010). Rethinking inequality: Dalits in Uttar Pradesh in the market reform era. Economic and Political Weekly, 45(35), 39–49.
10. Kurian, N. (2000). Widening regional disparities in India—Some indicators. Economic and Political Weekly, 35(7), 538–550. https://doi.org/10.2307/4408933
11. Kumar, N., & Rani, R. (2019). Regional disparities in social development: Evidence from states and union territories of India. South Asian Survey, 26(1), 1–27. https://doi.org/10.1177/0971523118825388
12. Ministry of MSME, Government of India. (2023). Brief industrial profile of Azamgarh district. Retrieved from https://dcmsme.gov.in
13. Nagaraja, K., & Veerabhadrappa, B. P. (2018). Inter-regional, inter-state and intra-state disparities in India—Causes, consequences and solutions. International Journal of Social Science and Economic Research, 3(1), 520–529.
14. Rao, M. K. (2023, February 19). Socio-economic overview of Dalits in India. Round Table India. Retrieved from https://www.roundtableindia.co.in/socio-economic-overview-of-dalits-in-india/
15. River Publishers. (2023). Agricultural productivity and regional disparity in Uttar Pradesh. Retrieved from https://journals.riverpublishers.com
16. Suryanarayana, M. H., Agrawal, A., & Prabhu, K. S. (2011). Inequality-adjusted Human Development Index for India's states. United Nations Development Programme, New Delhi.
17. UP Government. (2021). District human development report: Azamgarh (Unpublished report). District Planning Office, Azamgarh.
18. Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of patterns. Economic Development and Cultural Change, 13(4), 3–47. https://doi.org/10.1086/450136
19. World Bank. (2009). World Development Report: Reshaping Economic Geography. Washington, DC: World Bank.
20. Yadav, S. (2023). The problem of regional disparities: An overview in Indian context. Journal of Humanities and Education Development, 5(2), 14–16. https://doi.org/10.22161/jhed.5.2.3